नवभारत

जैव ईंधन नीति अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद

व्यापार प्रतिनिधि

मुंबई. इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के महानिदेशक संजय गंजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दिया जाना अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा. प्रगतिशील दृष्टिकोण वाली इस नीति से भारत में वैश्विक स्तर पर समान विकास के साथ तालमेल रखते हुए जैव ईंधन उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी. इस नीति में अखाद्य तिलहन, जले हुए खाद्य तेल और कम समय में तैयार होने वाली फसलों से बायोडीजल के उत्पादन के लिए सप्लाई चेन मेकैनिज्म स्थापित करने को भी प्रोत्साहित किया गया है. जैव सीएनजी, जो वाहन के ईंधन के लिए अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, एक उन्नत ईंधन के रूप में चिन्हित की गई है.

देश को होगा दूरगामी लाभ

ईंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ संजय गंजू ने कहा कि इस नीति के कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ी के ईंधन एथनॉल के उत्पादन से संबंधित हैं. द्वितीय पीढ़ी बायोरिफाइनरीज की स्थापना से किसानों को अतिरिक्त आय के अलावा खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार भी उपलब्ध होंगे. नीति में द्वितीय पीढ़ी एथनॉल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अनेक प्रावधान किए गए हैं. सरकार तेल विपणन कंपनियां भी 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 द्वितीय पीढ़ी बायोरिफाइनरीज स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं. पुणे स्थित प्राज इंडस्ट्रीज को इनमें से दो संयंत्र स्थापित करने हेतु चुना गया है.

प्रथम पीढ़ी एथनॉल के संबंध में अभी तक केवल खांड (मलैसिज) से उत्पादित एथनॉल को ही पेट्रोल में मिलाने की अनुमति थी. नई नीति में यह रोक हटा दी गई है. अब प्रथम पीढ़ी ईंधन एथनॉल को दूसरे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है जिनमें गन्ने के रस, बी हेवी खांड, मक्का, कसावा के साथ-साथ खराब अनाज जैसे कि गेहूँ, टूटे चावल, सड़े आलू और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अन्य वस्तुएं सम्मिलित हैं. इससे किसानों को मांग का ख्याल किए बगैर उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी. वर्धित सम्मिश्रण और स्थानीय स्तर पर उत्पादित एथनॉल के संयोजन में ऐसी क्षमता है जिससे देश के सम्मुख मौजूद अनेक अहम मुद्दों का समाधान हो सकता है. कृषक समुदाय के लिए कृषि अपशिष्ट आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत बन रहा है, इसलिए इनके जलाने की जरूरत नहीं रहेगी. जीवाश्म ईंधन के साथ मिश्रित एथनॉल का प्रयोग अपने-आप में कार्बन उत्सर्जन में कमी करता है.

LOCAL BUSINESS

बचेगी विदेशी मुद्रा

कृषि अपशिष्ट से तैयार द्वितीय पीढ़ी के एथनॉल को, जिसे एक उन्नत जैव ईंधन माना जाता है, इस नीति में और ज्यादा प्रधानता दी गई है. इसका सबसे प्रत्यक्ष फायदा यह है कि आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी. 150 करोड़ लीटर एथनॉल की अपेक्षित आपूर्ति के फलस्वरूप 2017-18 में 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है. भारत में पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथनॉल की मौजूदा माँग 10% है जिसमें से 5% से भी कम की पूर्ति हो रही है. लेकिन यह राष्ट्र 20% के अकांक्षापूर्ण मिश्रण अनुपात हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है.

Navabharat Mumbai Edition
2 July, 2018 Page No. 7
Powered by : erelego.com